

व्यापार-तकनीक सहयोग पर फोकस

भारत-ईयू एफटीए आर्थिक अवसरों का बड़ा द्वार खोल सकता है : जयशंकर

बसेल्स, 17 मार्च. भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने की दिशा में अहम प्रगति देखने को मिली है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बसेल्स दौरे के दौरान यूरोपीय संघ (ईयू) के शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को केंद्र में रखा गया.

यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही है और देश मजबूत व्यापारिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं. इस दौरान उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठकों



में व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत-ईयू एफटीए दोनों पक्षों के लिए आर्थिक अवसरों का बड़ा द्वार खोल सकता है और यह साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगा.

जयशंकर ने कहा कि एफटीए को अंतिम रूप देना भारत-ईयू संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो न केवल आर्थिक क्षमता को उजागर करेगा बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी गहराई देगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एफटीए के

टैटेंट मोबिलिटी और स्किल्स के आदान-प्रदान को भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा बताया गया. भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) को बढ़ावा देने और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने तथा सूचना सुरक्षा समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी जोर दिया गया.

लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए दोनों पक्षों को व्यावहारिक कदम उठाने होंगे. इसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ तकनीकी सहयोग को मजबूत करना शामिल है.

नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2025 सम्मान

भुवनेश्वर, 17 मार्च। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी को मशहूर केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2025 दिया गया। यह अवॉर्ड श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहन मुनासिंघे ने आइआइटी, केआईएसएस और केआईएमएस के फाउंडर डॉ. अच्युत सामंत की मौजूदगी में दिया। इंस्टीट्यूशन के सीनियर अधिकारी और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और जाने-माने लोग इस फंक्शन में शामिल हुए।

इस अवॉर्ड में श्रीमती अंबानी के बेहतरीन मानवीय कामों और रिलायंस फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, हेल्थकेयर, गांवों में बदलाव, महिलाओं को मजबूत बनाने और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने



के जरिए सामाजिक विकास में उनके अहम योगदान को पहचान दी गई। अपनी स्पीच में, श्रीमती अंबानी ने कहा कि डॉ. सामंत ने शिक्षा के दो मॉडल मंदिर बनाए हैं- आइआइटी और केआईएसएस ये दोनों इंस्टीट्यूशन हमारे देश के लिए गर्व की बात हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मशहूर केआईएसएस ह्यूमैनिटेरियन

रुपया दो पैसे हुआ मजबूत

मुंबई, 17 मार्च. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 1.75 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 92.2825 रुपये का बोला गया. पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 92.30 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही थी. रुपये में आज उतार-चढ़ाव रहा. यह 14 पैसे लुढ़ककर 92.44 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और दोपहर से पहले 92.4750 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गया था. कारोबारियों ने बताया कि निजी और सार्वजनिक बैंकों की डॉलर खरीद बढ़ाने से भारतीय मुद्रा को मजबूती मिली और कारोबार की समाप्ति पर यह 92.2825 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुई. भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से रुपये पर दबाव रहा.

बैठक से पहले बाजार में तेजी, निवेशक सतर्क

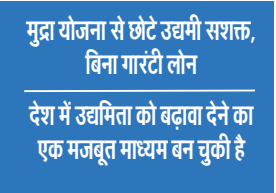


इसके साथ ही मध्य-पूर्व में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी की मांग को बढ़ावा दिया है. ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम से बचने के लिए कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं में मजबूती दर्ज की गई.

सोना 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया, जबकि चांदी में भी 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली. विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अहम बैठक से पहले बाजार में अस्थिरता बढ़ी है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस तेजी के पीछे कई वैश्विक कारक काम कर रहे हैं. सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी ब्याज दर बैठक है, जो 17-18 मार्च को होने वाली है. इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर लिए जाने वाले फैसलों पर पूरी दुनिया के निवेशकों की नजरें टिकी हैं. अगर फेड ब्याज दरों को स्थिर रखता है या महंगाई के दबाव का संकेत देता है, तो इसका असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है.

पीएमएमवाई से करोड़ों को मिला कारोबार का मौका : सीतारमण



मुद्रा योजना से छठे उद्यमी सशक्त, बिना गारंटी लोन देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन प्रमुख श्रेणियां- शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,001 से 5 लाख रुपये तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपये तक)— विभिन्न चरणों के व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करती हैं. यह संरचना नए उद्यमियों को शुरुआत करने से लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने तक निरंतर सहयोग प्रदान करती है. 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि लोन रिकवरी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. शिशु श्रेणी में गैर-निष्पादित संपत्तियां 12.4 प्रतिशत, किशोर में 9.4 प्रतिशत और तरुण में 7.92 प्रतिशत दर्ज की गई हैं.



की उपलब्धियों और प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यह योजना देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत तीन प्रमुख श्रेणियां- शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,001 से 5 लाख रुपये तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपये तक)— विभिन्न चरणों के व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करती हैं. यह संरचना नए उद्यमियों को शुरुआत करने से लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार करने तक निरंतर सहयोग प्रदान करती है. 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि लोन रिकवरी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. शिशु श्रेणी में गैर-निष्पादित संपत्तियां 12.4 प्रतिशत, किशोर में 9.4 प्रतिशत और तरुण में 7.92 प्रतिशत दर्ज की गई हैं.

उन्होंने कहा कि बैंक इन बकाया ऋणों की वसूली के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिससे योजना की स्थिरता बनी रहे. सीतारमण ने 'तरुण प्लस' श्रेणी पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत पात्र उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पिछले 'तरुण' लोन का सफलतापूर्वक भुगतान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना अभी अपेक्षाकृत नई है और इसे प्रभावी रूप से आंकने के लिए समय की जरूरत है.

तीन दिन गिरावट के बाद शेयर बाजारों में तेजी

567 अंक पर चढ़ा संसेक्स

172 अंक पर आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 17 मार्च. घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही, हालांकि आईटी और एफएमसीजी कंपनियों में बिकवाली देखी गयी. बीएसई का 30 शेयर्स वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 567.99 अंक (0.75 प्रतिशत) चढ़कर 76,070.84 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी-50 सूचकांक भी



172.35 अंक यानी 0.74 प्रतिशत की बढ़त में 23,581.15 अंक पर पहुंच गया. ऑटो, धातु, मीडिया, रियलटी, वित्त, निजी बैंकों और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों में मजबूत लिक्वालि के बीच आईटी और एफएमसीजी कंपनियों के सूचकांक गिरावट में रहे. मझौली

और छोटी कंपनियों में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.03 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.65 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. संसेक्स की कंपनियों में इटरनल का शेयर लगभग पौने छह फीसदी मजबूत हुआ. टाटा स्टील में करीब साढ़े चार फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी रही. बीईएल, एलएंडटी और भारती एयरटेल के शेयर दो प्रतिशत से ज्यादा चढ़े. मारुति सुजुकी, इंडिगो, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ट्रेंट के शेयर एक से दो प्रतिशत के बीच मजबूत हुए.

चीन से व्यापार घाटा 9.5 लाख करोड़ के करीब

नई दिल्ली, 17 मार्च. भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है—तेजी से बढ़ता व्यापार घाटा. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से फरवरी के बीच भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर (करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये) के करीब पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. सरल शब्दों में कहें तो भारत चीन से जितना सामान खरीद रहा है, उसके मुकाबले बहुत कम सामान बेच पा रहा है.

जियो पेमेंट्स बैंक ने शुरु की यूपीआई कैश विड्रॉल सेवा

मुंबई, 17 मार्च. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने यूपीआई आधारित कैश विड्रॉल सेवा शुरू करने की घोषणा की है. जिसके तहत ग्राहक अब बिजनेस करिस्पोडेंट टचपॉइंट्स पर कोड स्कैन कर नकद ग्राहक अब मतलब बिना डेबिट कार्ड और पारंपरिक एटीएम होने के बाद भी ग्राहक अपना पैसा निकाल सकते.

बैंक के अनुसार, नई सेवा खासतौर पर ग्रामीण और अर्ध-

शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जहां ङ्कर पहुंच सीमित है. ग्राहक अपने ऐप के माध्यम से ट्रांज़ेक्शन ऑथराइज कर आसानी से नकद प्राप्त कर सकेंगे. जियो पेमेंट्स बैंक ने कहा कि कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा डिजिटल भुगतान और नकद उपयोग के बीच की दूरी को कम करेगी तथा पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सहायक वातावरण में यूपीआई अनुभव प्रदान करेगी.

नितिन नबीन की सदन में क्या स्थिति होगी?

नई दिल्ली. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्यसभा को लिए निर्वाचित हो गए हैं. बिहार में पांच सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए ने सभी सीट जीत लीं.नितिन नबीन एनडीए के नंबर एक उम्मीदवार थे.अब वे उच्च सदन में आएंगे.उनको विधायी कामकाज का लंबा अनुभव है.वे 2006 से लगातार विधायक रहे हैं.राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अब वे बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देगे.

कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख को उस सीट से चुनाव लड़ना जाएगा.वे बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे.गौरतलब है कि मयूख का विधान परिषद का कार्यकाल



जून में समाप्त हो रहा है.बहरहाल, अब बड़ा सवाल यह है कि नितिन नबीन संसद में पहुंचें हैं और उच्च सदन में बैठेंगे तो वहां

लोकसभा में मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी आगे बैठेंगे हैं.दूसरा सवाल यह है कि क्या नितिन नबीन को सदन का नेता बनाया जा सकता है? ध्यान रहे अभी जेपी नन्हा सदन के नेता हैं लेकिन वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं.यानी दोहरी जिम्मेदारी है.दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे सदन में कांग्रेस के नेता हैं. सो, क्या भाजपा अपने अध्यक्ष को सदन का नेता बना सकती है?

उनको क्या स्थिति होगी ?

भले उम्र और अनुभव में नितिन नबीन बाकी लोगों से कम हैं लेकिन उनका पद बहुत बड़ा है.वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे उनके भी बांय हैं.

हालांकि मोदी ने कभी यह बात जेपी नन्हा या अमित शाह के लिए नहीं कही थी कि वे उनके बांय हैं.चूँकि उनको नितिन

नबीन का कद बढ़ा करना है इसलिए यह बात कही.

सो, पहला सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री के बांय नितिन नबीन कहां बैठेंगे ? उनके लिए राज्यसभा में अगली पंक्ति में सीट बनानी होगी.सीट इसलिए बनानी होगी कि अगर किसी खास स्थिति में सभी बड़े नेता राज्यसभा में पहुंचें तो समस्या नहीं हो.

राहुल और निलंबित सांसदों का क्या होगा?

नई दिल्ली. अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद स्पीकर ओम बिरला लोट आए हैं. उनको अब रोजमर्रा के कामकाज के साथ दो अहम मसलों पर फैसला करना है. उनके सामने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पेश किया गया सभ्सर्वेसिव मोशन है और विपक्ष के आठ सांसदों के निलंबन का मामला है.

गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले चरण में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ बिना सबूत बात कहने, देश विरोधी ताकतों से संपर्क रखने और दूसरे कई आरोपों में सभ्सर्वेसिव मोशन पेश किया था. पहले इस तरह के मोशन के आधार पर सांसदों को हटया जा चुका है. हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार राहुल गांधी को हटाना चाहेगी. लेकिन संभव है कि मामले कमेटी को भेज कर उसकी रिपोर्ट के



आधार पर राहुल की निर्दा हो. दूसरी ओर सदन से निलंबित आठ सांसद लगातार मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठ कर प्रदर्शन करते हैं. बजट सत्र के पहले चरण में भी वे प्रदर्शन करते रहे थे. अब भी उनका प्रदर्शन चल रहा है. उनके मामले में भी लग नहीं रहा है कि

अभी तुरंत स्पीकर कोई फैसला करेंगे. इस सत्र के बचे हुए हिस्से में उनकी वापसी मुश्किल लग रही है.

हालांकि अगर विपक्ष लोकसभा के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर के सामने सरकार के संसदीय प्रबंधकों से बात करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है. अगर रास्ता नहीं निकलता है तो आठ निलंबित सांसदों में से चार चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं. उनके राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है. इसलिए संसद की सीढ़ियों पर बैठे रहने से बेहतर चुनाव के काम में लगना होगा. दोनों मामलों में क्या होगा यह सोमवार तक पता चलेगा.

जेना की एंट्री से ओडिशा भाजपा में बगावत

कद्दावर नेता जीवन प्रदीप दास ने पार्टी से दिया इस्तीफा



भुवनेश्वर. ओडिशा की राजनीति में शुरुवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब बालेश्वर के वरिष्ठ नेता जीवन प्रदीप दास ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया. उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब हाल ही में बीजद के पूर्व सांसद रवींद्र जेना के भाजपा में शामिल होने के बाद जिले की पार्टी इकाई में असंतोष की

चर्चा चल रही थी.

बताया जा रहा है कि बालेश्वर में बदलते राजनीतिक समीकरणों को लेकर जीवन प्रदीप दास और उनके समर्थक नाराज थे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, जेना के शामिल होने के बाद स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर खींचतान बढ़ गई थी.

तीन बार विधायक रह चुके हैं दास

जीवन प्रदीप दास बालेश्वर के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और वे तीन बार विधायक रह चुके हैं. ऐसे में उनका भाजपा छोड़ना जिले की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि वह किसी अन्य दल में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन उनके इस फैसले से आने वाले चुनावों से पहले बालेश्वर की राजनीति में नई हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

विशेष डीएमके ने 'केएमडीके' को दी दो सीटें, क्या कांग्रेस से बढ़ेगा मतभेद?

तमिलनाडु में भी अकेली पड़ जाएगी कांग्रेस!

चेन्नई. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने शुरुवार को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगी कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची (केएमडीके) के साथ सीट बंटवारे के समझौते को औपचारिक रूप दे दिया. समझौते के तहत केएमडीके को दो विधानसभा सीटें दी गई हैं.

यह समझौता चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में एम.के. स्टालिन और केएमडीके के महासचिव ई.आर. ईश्वरन की मौजूदगी में



हुआ. समझौते के अनुसार, केएमडीके के उम्मीदवार डीएमके के प्रतिष्ठित 'राइजिंग सन' चुनाव चिह्न पर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. सीट बंटवारे को बातचीत पूरी होने और गठबंधन की पुष्टि के बाद

हालिया स्थानीय और राष्ट्रीय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का हवाला देते हुए कम से कम 35 सीटों की मांग की है.

डीएमके नेतृत्व 234 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 180 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने के पक्ष में है. इसी वजह से दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहरता जा रहा है. इस बीच ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को 2021 विधानसभा चुनाव की तरह 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है.

कुछ नेता गठबंधन तोड़ने के पक्ष में

तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस और डीएमके के बीच का यह संघर्ष कहीं ना कहीं यह सवाल पैदा कर रहा है कि कांग्रेस राज्य में अकेली पड़ सकती है. अगर सीट वांटवारे को लेकर बात नहीं बनी तो कांग्रेस में कुछ नेताओं का समूह ऐसा है जिन्हें ज्यादा सीट चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह इस गठबंधन को तोड़ने के पक्ष में है. इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा कर रही हैं कि 2 मार्च की रात कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था.